भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4240

(दिनांक 26.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

कम्यूनिटी रेडियों कंटेट चैलेंज

4240. श्री भोजराज नागः

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

श्री कंवर सिंह तंवरः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कम्यूनिटी रेडियों कंटेट चैलेंज छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले, महाराष्ट्र के जलगांव जिले तथा उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार किस प्रकार स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने में योगदान देते हैं, जिससे उनकी आवाज बुलंद होती है तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में जमीनी समस्याओं का समाधान होता है;

(ख) क्या सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण तथा कृषि संबंधी समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए क्षेत्र-विशिष्ट की चुनौतियों से निपटने में कम्यूनिटी रेडियो की भूमिका बढ़ाने के लिए कोई पहल की है, तथा यदि हां, तो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले, महाराष्ट्र के जलगांव जिले तथा उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार तथा जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले, महाराष्ट्र के जलगांव जिले तथा उत्तर प्रदेश सहित कम्यूनिटी रेडियो कंटेट चैलेंज को अधिक समावेशी तथा प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए इसमें विविध क्षेत्रों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्यवार क्या उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(घ) सरकार का देश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले, महाराष्ट्र के जलगांव जिले और उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार और जिलावार जन स्वास्थ्य जागरूकता, ग्रामीण विकास और

किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए कम्यूनिटी रेडियो का उपयोग किस प्रकार करने का विचार है; और

(ङ) क्या छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में रेडियो स्टेशन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ड.) सामुदायिक रेडियो सामग्री प्रतिस्पर्धा देश के विभिन्न भागों में संचालित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) के लिए अपनी सृजनात्मकता, नवाचार और प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर है, ताकि राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करके मान्यता प्राप्त की जा सके। यह चुनौती वंचित समुदायों की आवाज़ को सशक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफार्म के रूप में कार्य करती है, जिन्हें अक्सर मुख्य मीडिया में नहीं सुना जाता है। क्षेत्र-विशिष्ट स्टोरीटेलिंग और सामग्री सृजन को प्रोत्साहित करके, यह पहल स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और सहभागी संचार को बढ़ावा देने में मदद करती है। सीआरएस द्वारा प्रसारित कार्यक्रम समुदाय के लिए प्रासंगिक होने चाहिए। विकासात्मक, कृषि, स्वास्थ्य, शैक्षिक, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण, सामुदायिक विकास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रोग्रामिंग में स्थानीय समुदाय की विशेष रुचियों और जरूरतों को दर्शाया जाना चाहिए। सामुदायिक सामग्री चुनौती को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि सभी परिचालन स्टेशनों को प्रतिस्पर्धा के बारे में सूचित किया गया, क्षेत्र-विशिष्ट क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ सीआरएस को सहायता प्रदान करना भी शामिल है। सामाजिक और विकासात्मक मुद्दों पर सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रभावी उपयोग के बारे में पूरे भारत में विभिन्न जागरूकता सृजन कार्यलाप आयोजित किए जा रहे है, जिससे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के जिलों सहित सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशन लाभान्वित हुए हैं।

केन्द्र सरकार, ब्राडकास्ट सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के पश्चात पात्र संस्थाओं को उनके इच्छित स्थानों पर सामुदायिक रेडियो स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। केन्द्र सरकार ने "भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान को सहायता" नामक एक केन्द्रीय

क्षेत्र स्कीम को भी मंजूरी दी है, जहां सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है (विवरण https://mib.gov.in पर उपलब्ध है)। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।

*****